

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास श्री राजकेश मीना आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या :- 129/2018

=

श्री नरपतसिंह पुत्र अभेसिंह जाति राजपूत निवासी गोधन तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

गण:

श्री कुशालसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी गोधन तहसील खींवसर जिला नागौर
श्री कालुराम पुत्र धर्मराम जाति विश्णोई निवासी ढींगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर
तहसीलदार खींवसर
उप पंजीयक खींवसर

वकील पक्षकारान

1. वकील प्रार्थी :- श्री मूलसिंह राठौड
2. अप्रार्थीगण :- (एक पक्षीय)

आवेदन अधीन धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

आदेश

दिनांक

प्रार्थी ने जरिये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र आवेदन अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अजैन्ट नेचर का होने से उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने से पूर्व हमें एक पक्षीय सुना जावे। प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली पर मौजूद रेकर्ड अनुसार उक्त प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई है की मौजा ढींगसरा के ख.न. 121/3 रकबा 78.11 बीघा की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे न किसी अन्य से करावे, एवं बैचान हस्तान्तरण, रहन आदी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व की यथारिथति बनाये रखें। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया गया।

23
सहायक क्लर्क
(SDO), खींवसर

सुविधा का संतुलन :-

इसमें यह देखा जाता है कि निषेधाज्ञा देने या न देने से किसी पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी या नहीं। जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किये जाने की दशा में अप्रार्थी सं. 1 व 2 से अधिक असुविधा प्रार्थी को होगी। क्योंकि उक्त विवादग्रस्त आराजी अविभाजित एवं शुद्धिकरण से वंचित है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अपूरणीय क्षति :-


जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है प्रार्थना पत्र को स्वीकार न किये जाने की दशा में केवल अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं होकर के साथ में ही प्रार्थी को भी विधिक हानी होकर अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। चूँकि प्रार्थी का वादग्रस्त में बंट व कब्जा काष्ठ होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

इस प्रकार उपरोक्त विप्लेषण से प्रा.पत्र के तीनों बिन्दु 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति यह तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य होने की वजह से स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश जारी किया जाता है कि :-


आदेश

अतः मौजा ढींगसरा के ख.न. 121/3 रकबा 78.11 बीघा की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे न किसी अन्य से करावे, एवं बैचान हस्तान्तरण, रहन आदी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व की यथास्थिति बनाये रखने के पूर्व आदेश दिनांक 13.12.2018 को ता-फैसला वाद तक स्थाई (**Confirm**) किया जाता है।

नोट:- उपरोक्त खसरा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।


राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खीवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : को सरे इजलास सुनाया गया।


राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खीवसर